विचार बिन्दु

अतिथि जिसका अन्न खाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। –अथर्ववेद

'जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे'

एक पुरानी हिंदी फिल्म सफर का यह गीत है :

''जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे
तुम दिन को कहो रात, तो रात कहेंगे''।

विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक जनप्रतिनिधियों, विशेषकर सत्ताधारी दल के प्रति पूर्ण समर्पण की प्रवृत्ति हो गई है, उससे तो यही पंक्तियां शत प्रतिशत इन पर लागू होती हैं। समर्पण का भाव केवल नीतियां बनाने में ही नहीं, अपितु उनके क्रियान्वयन के सम्बंध में निर्णय लेने में भी दिखाई देता है। यही नहीं, अपने अधीनस्थों के स्थानांतरण करने तक में यही प्रवृत्ति दिखाई देती है।

एक समय था जब भारतीय प्रशासनिक सेवा को 'स्टील फ्रेम' कहा जाता था। इसके अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि बिना किसी दबाव के, कानून नियम के अंतर्गत रहते हुए जनता के हित की बात करेंगे।उन्होंने प्रारंभिक कई सालों तक ऐसा किया भी था। धीर-धीरे अधिकारियों ने अपने विवेक को एक प्रकार से नेताओं के गिरवी ही रख दिया।

तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत के प्रशासनिक तंत्र का ढांचा तैयार किया था। उन्हें यह पता था कि जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी स्तर के हों, अपनी स्वार्थ सिद्धी, अफसरशाही के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। इसी पर अंकुश लगाने की दृष्टि से अखिल भारतीय सेवाओं को बनाया गया, जिनमें पुलिस सेवा एवं प्रशासनिक सेवा प्रमुख थीं। इनकी स्थापना अखिल भारतीय स्तर और प्रत्येक राज्य के स्तर पर भी की गई। इसके माध्यम से देश के एकीकरण की बात को भी बल दिया जाने का उद्देश्य था। प्रारंभिक अवस्था में जनप्रतिनिधि इस बात पर बल दिया करते थे कि संविधान सम्मत राय प्रत्येक स्तर के अधिकारी, स्पष्ट रूप से कहें एवं लिखें। उसके बाद अंतिम निर्णय निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिनिधियों के ऊपर छोड़ा जाता था। यह देखा गया है कि बहुत कम जनप्रतिनिधियों में यह नैतिक बल होता है कि वह लिखित में अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किसी सही प्रस्ताव को ठुकरा सकें।

आवश्यक है कि, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण समन्वित रूप से कार्य करें ताकि योजना का लाभ, समाज के वंचित वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। धीरे-धीरे समय के साथ ,स्वार्थ पूर्ण व्यवहार बढ़ता गया और सामान्य जनता का हित गौण हो गया। जनप्रतिनिधि गणों को तो प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव में जाना होता है, जिसके कारण कई बार वे ऐसे निर्णय भी लेते हैं जो उपयुक्त ना हों। इस प्रकार के निर्णय के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव का अध्ययन करना एवं उसके संबंध में कानून सम्मत दृष्टिकोण व्यक्त करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। वे कुछ सालों पहले तक तो यह काम भली- भांति करते थे। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया कि अधिकारीगण नेताओं के उचित -अनुचित सभी प्रकार के काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। आजकल यह एक सामान्य बात हो गई है कि कनिष्ठ कर्मचारियों तक के स्थानांतरण मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री तक के स्तर पर होने लगे हैं। गत कुछ वर्षों से तो विधायकों की डिजायर से ही स्थानांतरण होने लगे हैं। जबकि यह काम करने का अधिकार एवं दायित्व अधिकारियों का है। जब अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी , विभागाध्यक्ष एवं सचिव के नियंत्रण में नहीं होंगे तो फिर उन से काम लेना किसी भी प्रकार से उनके के लिए संभव नहीं हो पाएगा।यही कारण है कि वरिष्ठ अधिकारियों का अपने कार्य पर नियंत्रण कम होता गया। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।

मसूरी एवं अन्य राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में आज भी अधिकारियों को सही एवं स्पष्ट बात करने की सलाह दी जाती है।प्रशिक्षण में तो वही बातें बताई जाती हैं जो पहले के समय में बताई जाती थीं, किंतु शायद अब अधिकारीगण तथाकथित महत्वपूर्ण पोस्टिंग के लोभ में, वह सब करने को तैयार हो जाते हैं ,जो उन्हें नहीं कर ने चाहिए। ऐसा करके वे न केवल जनहित के विरुद्ध काम करते हैं, बल्कि अपनी अंतरात्मा को भी गिरवी रखने का काम करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, गलत काम करने हेतु सामान्यतया कोई भी मंत्री लिखित में आदेश जारी नहीं करते हैं। वे अधिकारियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम करने के आदी हो गए हैं। समस्या यह है कि अधिकारी गण इस काम के लिए अपना कंधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में सुशासन नहीं होने का दोष केवल जनप्रतिनिधियों पर डालना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि कोई काम करने योग्य नहीं था एवं अनुचित था, तो वही काम फिर किसी भी मंत्री के कहने पर क्यों और कैसे कर दिया जाता है? यदि काम सही था तो प्रारंभिक अवस्था में ही समय पर कर दिया जाना चाहिए था और यदि काम गलत था, तो फिर उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर किसी के कहने पर क्यों कर दिया जाता है?

तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत के प्रशासनिक तंत्र का ढांचा तैयार किया था। उन्हें यह पता था कि जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी स्तर के हों, अपनी स्वार्थ सिद्धी, अफसरशाही के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। इसी पर अंकुश लगाने की दृष्टि से अखिल भारतीय सेवाओं को बनाया गया, जिनमें पुलिस सेवा एवं प्रशासनिक सेवा प्रमुख थीं।

किसी प्रकरण की एफ आई आर थाने द्वारा दर्ज नहीं की जाती, वहीं किसी जनप्रतिनिधि के कहने पर तत्काल दर्ज कर दी जाती है।किसी भी भूमि का पट्टा सामान्य तरीके से जारी नहीं हो रहा है तो उच्च स्तर से कहने पर वह तत्काल जारी हो जाता है।किसी छात्र को यदि किसी संस्थान में प्रवेश नहीं मिल रहा है तो फिर मंत्री या जनप्रतिनिधि के कहने पर कैसे हो जाता है? इसी प्रकार चाहे बैंक से लोन लेने का प्रकरण हो, सरकार में किसी प्रकार का ठेका प्राप्त करने का प्रकरण हो, किसी प्रकार के स्थानांतरण का प्रश्न हो, किसी विभाग में खरीद का मामला हो, इन सब में अधिकारीगण अपनी भूमिका को लगभग बिलकुल छोड़ चुके हैं।जिस कार्य को करने के लिए उन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है वह निर्भीक होकर पत्रावली पर लिखें और प्रस्ताव प्रस्तुत करें वे ऐसा नहीं करने लगे हैं। आजकल तो अधिकारी इतने समझदार हो गए हैं कि मंत्रियों की मंशा को भांप कर, उसी के अनुसार काम करना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वह जनता के हित के विरुद्ध ही क्यों न हो? ऐसा करके, वे कमजोर व्यक्ति के हित के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं। ऐसा कृत्य उनके लिए दंड का कारण बनना चाहिए। प्रश्न यह भी है कि दंड देने के लिए जिन व्यक्तियों को कार्रवाई करनी चाहिए वही इस प्रकार के कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य करते हैं। अधिकारियों में संगठन का अभाव इसका एक कारण है। वे एक दूसरे को हटाकर उसके स्थान पर पदस्थापन पाने के प्रयास में लगे रहते हैं और इसी का लाभ जनप्रतिनिधि सामान्यतया उठाते हैं।

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में समन्वय तो शासन के प्रत्येक स्थल पर आवश्यक है चाहे वह पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला हो या राज्य स्तर पर हो। जनप्रतिनिधि और अधिकारी ,कार्यपालिका के दो पहिए की तरह होते हैं जिनके परस्पर उपयुक्त समन्वय के आधार पर ही विकास कार्यों की गाड़ी सुगमता से चलती है। जनप्रतिनिधि जनता के हित को ज्यादा भली-भांति समझ सकते हैं एवं उनका सीधा जुड़ाव जनता से होता है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनता के मुद्दों को अधिक अच्छी तरह से समझ कर उनके निराकरण का प्रयास करेंगे। यहां तक तो ठीक है, किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब जनप्रतिनिधि जनता के हित को सर्वोपरि मानने के स्थान पर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा करते समय वह उस व्यक्ति के हित की बलि दे देते हैं जो प्रशासनिक अथवा राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है कि वह अपने दम पर अपना काम सरकारी कार्यालयों से करवा सके। अधिकारियों का काम यह देखने का होता है कि वह निर्णय विधि सम्मत है या नहीं एवं क्या उससे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का लाभ होगा या नहीं ? नियमों की परिधि में रहते हुए अपने सुझाव और प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों को देने के लिए वे न केवल स्वतंत्र हैं, अपितु ऐसा करना उनका कर्तव्य भी है।

उच्च स्तरीय संस्थाएँ, यहां तक कि संवैधानिक संरक्षण प्राप्त संस्थाएँ भी सत्ता धारी दल के सम्मुख नत- मस्तक हो गई हैं।

सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि विभाग जिस प्रकार से चुनावों से ठीक पहले विपक्षी दलों के कुछ गिने चुने नेताओं पर छापेमारी की कार्रवाई करते हैं, उससे लगता है कि वह निष्पक्ष रूप से निर्णय नहीं ले कर केवल राजनीतिक आकाओं से मिले निर्देश के आधार पर कार्यवाही करते हैं। अन्यथा, यह कैसे संभव है कि अधिकांश कार्रवाई केवल विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध ही हो?

सरकार पहले तो रीढ़ विहीन लोगों को इन संस्थाओं में उच्च पदों पर पद स्थापित करती है एवं उसके बाद यह मनमाने तौर पर इनसे कार्य कराती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो, सीवीसी हो, यहां तक कि न्यायपालिका भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। शिक्षाविदों के समर्पण की स्थिति तो यह है कि कर्नाटक के पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ में यह तक लिख दिया गया है कि कैसेअंडमान निकोबार के जेल से वीर सावरकर बुलबुल पर बैठकर भारत के अन्य भागों में गए थे। भारतीय व्यवस्था में इस प्रकार की स्थिति भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है।सत्ताधारी दल में परिवर्तन तो लोकतंत्र में अवश्यंभावी है और यदि अपने दलों के आधार पर अधिकारियों का उपयोग होता रहा एवं अधिकारीगण भी अपने को बचाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे तो फिर ये संस्थाएँ सत्ताधारी दलों के स्वार्थों की पूर्ति का हथियार मात्र बन कर रह जाएंगी।

गत कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि न केवल सरकारी अधिकारी जो कि सीधे रूप से जनप्रतिनिधियों के अधीन काम करते हैं एवं जिन पर सरकार का नियंत्रण है, वे बिना कोई प्रतिरोध किए जनप्रतिनिधियों के उचित- अनुचित आदेश मानने को न केवल तैयार रहते हैं अपितु संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी समर्पण हेतु लालायित रहते हैं। ये सब सेवा से निवृत्ति के बाद किसी आयोग का अध्यक्ष बनने, राज्य सभा का सदस्य या राज्यपाल बनने के मोह के कारण ऐसा करते हैं। संवैधानिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति भी यदि पूर्ण निष्पक्षता के साथ निर्णय न लें, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा क्योंकि सरकार चाहे तब भी ,उनको नहीं हटा सकती।

निर्वाचन आयोग द्वारा सत्ताधारी दल की सुविधा के अनुसार चुनाव का कार्यक्रम बनाया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात विधानसभा के चुनाव घोषित हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया ताकि सत्ताधारी दल के नेताओं को और घोषणाएँ करने का अवसर मिल जाए। चुनावी बांड की योजना जिसमें पारदर्शिता का अभाव है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। नोटबंदी का निर्णय हो अथवा लॉकडाउन लगाने का निर्णय जैसे सभी निर्णयों का प्रतिरोध न करके उच्च स्तर की संस्थाओं में बैठे लोगों ने फिल्म की इन्हीं पंक्तियों को सच सिद्ध किया है कि वे रात को दिन और दिन को रात कहने में भी संकोच नहीं करते हैं।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

पशुओं के चारे पर भी पड़ी महंगाई की मार

सांभरझील, (निसं)। गुढा साल्ट मुख्यालय सहित आस-पास के क्षेत्र में इन दिनो पशुओं के लिए चारे की कटाई ट्रेक्टर की सहायता से की जा रही है। गौरतलब है कि महंगाई की मार अब पशुओं के चारे पर भी पड़ रही है। किसान रामकुमार लोरा ने बताया कि पशुओं का सूखा चारा इन दिनो 700 रुपये मण के हिसाब से बिक रहा है। इसलिए पशु पालक किसानों के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है। महंगा चारा पशुओं को मोल खरीदकर खिलाना पशुपालकों के बूते से बाहर दिखाई दे रहा है।

सूखे चारे के दाम पहली बार इतने महंगे बताए जा रहे हैं। एक एकड़ सूखे चारे की औसत लगाई जाए तो एक मन 40 किलो ग्राम सूखा चारा करीब 700 रुपये में पड़ रहा है। आसमान छूते इन भावों ने पशुपालक किसानों की चिता बढ़ा दी है।

किसानों का कहना है कि उन्होंने इतने महंगे दाम पहले कभी नहीं देखे। सात सौ रूपए मण के भाव देख किसान घास की खुदाई में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चारे के दामों में यही बढ़ोतरी रही तो पशुओं को चारे का संकट पैदा हो सकता है।

चारे के बढ़े दामों के कारण कुछ पशुपालक किसान अपने पशुओं को बेचने की सोचने लगे हैं। सोहन देवी, ओमप्रकाश,नीतेश लोरा,गजराज सहित कई किसान भाई और महिलाए चारा एकत्रित करते नजर आए।

सांभर में खेत पर चारा एकत्रित करते किसान।

सोनू हुडील ने गोवा में बॉलीवॉल नैशनल गेम में राजस्थान का नाम रोशन किया

झुंझुनूं, (निसं)। गोवा में हुई नेशनल बॉलीवॉल गेम्स में नागौर जिले के गांव भींचरों का बास की बेटी सोनू हुडील ने प्रथम स्थान पर रहकर देश का एवं राजस्थान का नाम रोशन किया।

एक किसान रामेश्वर लाल की बेटी ने गोवा में परचम लहराया। जिसमें देवसेना टीम झुंझुनूं के पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे।

■ सोनू हुडील ने गोवा में वॉलीबॉल नेशनल गेम में राजस्थान का नाम रोशन किया

देवसेना संगठन झुंझुनूं के जिलाध्यक्ष रोहिताश गुर्जर डोई ने बधाई भी दी और साथ ही बताया कि आज के समय में बेटियों ने यह साबित करके दिखाया की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। अगर उनको सही दिशा एवं सही मार्गदर्शन मिले।

मैं सभी बहन बेटियों के परिवारजनों से अनुरोध करता हूं कि उनको सही दिशा एवं सही मार्गदर्शन दें ताकि देश का समाज का नाम रोशन करें।

इस मौके पर कोच रोहिताश गुर्जर खोरा, कोच कुलजीत कौर, देवसेना संगठन झुंझुनूं से जिला सचिव सिंगर देव गुर्जर बागोरा, नवलगढ़ तहसील महामंत्री बलवीर सिंह छावड़ी, जीतू गुर्जर, भास्कर बावता, दीपक गुर्जर, लाला गुर्जर अन्य लोग मौजूद थे। देवसेना संगठन झुंझुनूं के जिला सचिव सिंगर देव गुर्जर बागोरा ने बताया कि इन बेटियों को समस्त देवसेना टीम झुंझुनूं के द्वारा बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।

साथ ही उज्जवल भविष्य और भविष्य में ऐसे ही देश एवं राजस्थान का नाम रोशन करते रहे।

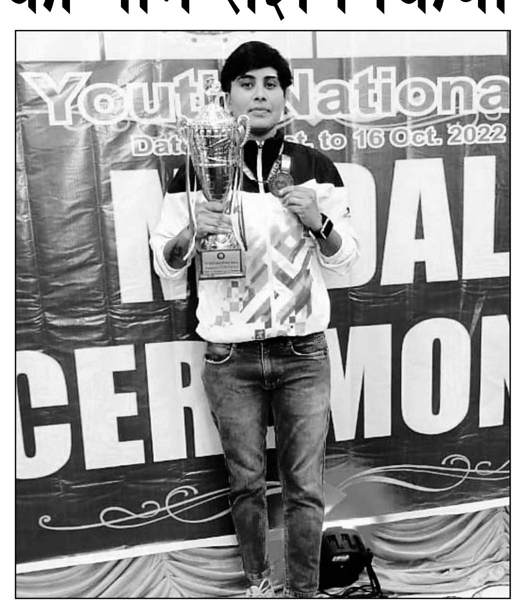

पदक जीतने के बाद खिलाड़ी सोनू हुडील खुश नजर आईं।

मेघवाल को भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान

समर्पण संस्था ने पन्नालाल मेघवाल को समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया।

जयपुर, (कासं)। समर्पण संस्था द्वारा रविवार को जयपुर में आयोजित समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए सिक्किम के पूर्व राज्यपाल जस्टिस एस. एन. भार्गव ने भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान- 2022 से सम्मानित किया गया।

संस्थापक अध्यक्ष डॉ. दौलतराम माल्या ने बताया कि पन्नालाल मेघवाल की कला एवं संस्कृति में बारह पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में 500 से अधिक आलेख प्रकाशित हुए हैं। उनकी पुस्तकों एवं आलेखों से देश-विदेश के सुधि पाठक, कला एवं संस्कृति प्रेमी, शोधार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी अध्ययन करके लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेघवाल की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के मांड गीत, राजस्थान शिल्प सौंदर्य प्रतिमान, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम, दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य, राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं, दी हैंडीक्राफ्ट्स आफ राजस्थान, राजस्थान कथौड़ी जनजाति, राजस्थान कला एवं संस्कृति के विविध आयाम और राजस्थान कथौड़ी जनजाति कला एवं परंपरा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

चार सौ वर्ष पुराने ऐतिहासिक तालाब पर भू माफिया ने तारबंदी की

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड के पपुरना गांव में ऐतिहासिक तालाब पर भूमाफियाओं द्वारा तारबंदी कर कब्जा करने के प्रयास के मामले को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि पपुरना से डाबला जाने वाली सड़क पर दहलासरी के नाम से ऐतिहासिक तालाब है। जिसे दहलासरी (महाजन) समाज के लोगों ने करीब चार सौ वर्ष पूर्व बनाया था।

■ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, प्रशासन पर लगाए मिलीभगत के आरोप

इस तालाब पर पूर्व में शिवरात्रि के मेले पर कुश्ती का आयोजन होता था तथा तीज के त्यौहार पर नवविवाहित जोड़े झूला झूलने की परंपरा भी थी। तालाब के पास में सती माता का मंदिर व शमशान भूमि भी है। जहां ग्राम पंचायत की ओर से महिला व पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय बनवाए गए हैं। इसके अलावा आवारा पशुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई हुई है। सेठों ने पूर्व में राहगीरों के ठहरने के लिए इस ऐतिहासिक तालाब का निर्माण करवाया था। जिस पर कुछ दिनों से बाहर के भूमाफिया की नजर इस ऐतिहासिक तालाब की बेशकीमती जगह पर टिकी हुई है। जिन्होंने पोल लगाकर तारबंदी कर कब्जा करने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक तालाब पर कब्जे की सूचना को लेकर सैंकड़ों ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों के विरोध के चलते भूमाफिया ने तारबंदी का काम राक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में दो दिन पूर्व एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन की मिलीभगत के चलते इस ऐतिहासिक तालाब पर भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि इस ऐतिहासिक तालाब पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध भी जताया। इस मौके पर रमेश गुप्ता, पवन दाधीच, भागीरथ मेघवाल, मानप्रकाश कुमावत, संजयदेव गुर्जर, दुर्गा प्रसाद, नेमुद्दीन कुरैशी, उमाशंकर फरेरा, जगमाल महरानिया, अंजनी गुप्ता, उमराव मेघवाल, शुभम गुप्ता, धर्मपाल गुर्जर, कैलाश शर्मा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे।

पपुरना गांव के ग्रामीणों ने तालाब पर कब्जे के विरोध में प्रदर्शन किया।

राशिफल मंगलवार 18 अक्टूबर, 2022

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, अष्टेमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2079, पुष्य नक्षत्र गुरूवार प्रातः 8:02 तक, सिद्ध योग सांय 4:52 तक, कौलव करण दिन 11:58 तक, चन्द्रमा कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-तुला, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मिथुन, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-कन्या, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज शुक्र तुला राशि में रात्रि 9:39 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:22 से 10:47 तक, लाभ-अमृत 10:47 से 1:37 तक, शुभ 3:02 से 4:27 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:31, सूर्यास्त 5:52

मेष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले सुसंदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले सुसंदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में

कर्क
मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

सिंह
मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

कन्या
मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है।

वृश्चिक
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी और उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

धनु
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी और उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

मकर
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी और उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी और उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।